

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रलिस के लयि:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ।

मेन्स के लयि:

कल्याणकारी योजनाएँ, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप ।

चर्चा में क्योँ?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY- G) की पूरुणता दर 67.72% है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) जसिकी शुरुआत एक वर्ष पूरुव हुई थी, 50% पूरुणता दर के साथ पछिड रही है ।

दोनों योजनाओं में देरी का प्रमुख कारण:

- **महामारी:**
 - सरकारी अधिकारी PMAY-U में देरी के लयि **कोवडि-19 महामारी** को ज़मिमेदार ठहराते हैं
 - कोवडि-19 महामारी से पहले स्वीकृत घरों की पूरुणता दर लगभग 80% थी ।
- **राज्योँ द्वारा खराब कारयान्वयन:**
 - लक्षति इकाइयोँ का 70% हसिसा छह राज्योँ में है- जसिमें पश्चमि बंगाल, मध्य प्रदेश, बहार, ओडशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ शामिल हैं ।
 - इनमें से केवल दो राज्योँ- उत्तर प्रदेश और पश्चमि बंगाल की पूरुणता दर राष्टरीय औसत से अधिक है ।
 - बहार में सबसे कम पूरुणता दर है ।
- **स्पष्ट शीर्षकोँ और दस्तावेजोँ का अभाव:**
 - शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट शीर्षक और अन्य भूमि दस्तावेजोँ की कमी जैसे मुद्दे सामने आते हैं, परणामस्वरूप इसकी गति और धीमी हो गई ।
 - यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी है ।
- **दो राज्योँ में केंद्र द्वारा नधि आवंटन को रोकना:**
 - पश्चमि बंगाल में यह आरोप लगाया गया था कविरतमान राज्य सरकार इस योजना को **बांग्ला आवास योजना** के रूप में फरि से तैयार कर रही है ।
 - छत्तीसगढ के लयि नधिरोक दी गई क्योँकि राज्य, योजना के लयि योगदान का अपना हसिसा देने में वफिल रहा ।
 - केंद्र 60% राशिका भुगतान करता है और राज्योँ को लागत का 40% वहन करना पड़ता है ।

PMAY-G योजना :

- **लॉन्च:** इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लयि आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरु कया गया था । ज्ञात हो कि पूरुववर्ती 'इंदरि आवास योजना' (IAY) को 01 अपरैल, 2016 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनरुगठति कया गया था ।
- **शामलि मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय ।
- **उद्देश्य:** मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीरुण-शीरुण घरों में रह रहे हैं, को बुनयादी सुवधियों के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना ।
 - जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयोँ के नरिमाण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूरुण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना ।
- **लाभार्थी:** अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति से संबंधति लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, वधिया महलाएँ, रक्षाकर्मीयोँ के परजिन, पूरुव सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलोँ के सेवानवृत्त सदस्य, वकिलांग व्यक्ती तथा अल्पसंख्यक ।

- **लाभार्थियों का चयन:** तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से- सामाजिक आर्थिक जातिजनगणना 2011, ग्राम सभा, और जियो-टैगिंग।
- **कॉस्ट शेयरिंग:** यूनटि सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- **उपलब्धियाँ:**
 - इसे 2.7 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
 - केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार, अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है।
 - यह लक्ष्य का 67.72 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U):

- **लॉन्च:**
 - 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
- **कार्यान्वयन:**
 - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- **वशिष्टाएँ:**
 - यह शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करता है।
 - इस मशिन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है (जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जैसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है)।
 - PMAY(U) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
 - यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।
 - वकिलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पछिड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
- **उपलब्धियाँ:**
 - इसकी शुरुआत 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ की गई थी।
 - केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ताज़ा आँकड़ों के मुताबिक, अब तक सरिफ 60 लाख यूनटि का निर्माण ही पूर्ण हो पाया है।

स्रोत: द हिंदू